



‘ग्रेट फ्लॉप को महासफलता कैसे साबित करते हैं, कोई गहलोत से सीखे’

पटना में गहलोत ने लालू यादव के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण किया, पर, पटना, जयपुर और दिल्ली में उनका प्रचार तंत्र यह स्थापित करने में लगा रहा कि कैसे गहलोत ने कांग्रेस की डूबती नैया बचा ली

-नेपु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। यह कहानी है कि कैसे कांग्रेस और उसके नेताओं ने बिहार की स्थिति को बिगाड़ दिया और एक-दूसरे के खिलाफ काम किया।

राहुल गांधी ने अपने प्रिय “अल्लूवेरा” को बिहार का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया।

वे घमंडी और अडिगल हैं, राजनीति कैसे काम करती है, कैसे लेन-देन और समझौते होते है, उन्हें इसकी समझ नहीं है।

उन्होंने राहुल गांधी को यह विश्वास दिलाया कि वे तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ कड़ी सौदेबाजी कर रहे हैं और अंततः उनसे अच्छी डील हासिल कर लेंगे।

उन्होंने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव

- दबाव में तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो उन्होंने घोषित किया, किन्तु बदले में कांग्रेस के लिए कुछ हासिल नहीं कर पाए, लालू यादव से।
- न तो उपमुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन ले सके और ना ही आठ “फ्रैंडली कॉन्टेस्ट” वाली सीटों पर से आरजेडी के उम्मीदवार बैठ सके।
- उनकी सोशल मीडिया टीम अब यह स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि गहलोत पुनः सोनिया गांधी की गुड बुक्स में हैं तथा सोनिया उन्हें सीधे फोन करके निर्देश देती हैं। यही नहीं, यदि वे पटना में हस्तक्षेप नहीं करते तो कांग्रेस का बंटोधार तय था।
- असलियत यह है कि बिहार प्रभारी अल्लूवेरा ने लालू, तेजस्वी से संबंध इतने खराब कर लिये थे कि वेणुगोपाल ने स्वयं निर्देश दिया, पटना जाने के लिए, किन्तु वहाँ जाकर गहलोत कुछ भी हासिल नहीं कर पाए।

की घोषणा करने से इनकार कर दिया। जब यादवों का दबाव बढ़ा तो के. सी. वेणुगोपाल एक्शन में आए और अशोक गहलोत को एक वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में पटना भेजा। दिलचस्प बात यह है कि जब

गहलोत लालू यादव से मिलने गए तो तेजस्वी भी वहाँ थे। तेजस्वी ने अल्लूवेरा को कमरे में घुसने तक की अनुमति नहीं दी और उन्हें बाहर ऑफिस में इंतजार करने के लिए कहा।

ये थीं गहलोत की कांग्रेस को

बचाने और तेजस्वी को नियंत्रण में रखने की कोशिशें!

बैठक में लालू ने गहलोत से पूछा कि वे तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति मुर्मू राफेल में उड़ान भरेंगी

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू बुधवार को भारतीय वायु सेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेंगी। राष्ट्रपति इससे पहले वायु सेना के सुखेई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं।

राष्ट्रपति सचिवालय ने मंगलवार को बताया कि श्रीमती मुर्मू बुधवार को अंबाला वायु सेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी।

- वे पूर्व में सुखेई लड़ाकू विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं।

राफेल भारतीय वायु सेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है और इसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सूत्रों के अनुसार अंबाला वायु सेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति को सम्मान स्वरूप गार्ड आफ ऑनर दिया जायेगा। राष्ट्रपति को राफेल विमान के बारे में भी जानकारी दी जायेगी। इसके बाद वह विमान में उड़ान भरेंगी।

केन्द्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन की सिफारिशों के लिए मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ-साथ उसके काम के दायरे

- जस्टिस रंजना देसाई अध्यक्ष होंगी, 18 माह में रिपोर्ट।

और शर्तों को भी मंजूरी दे दी। आयोग को अठारह महीने में रिपोर्ट देनी होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी। भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का अस्थायी सदस्य बनाया गया है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन इसके सदस्य सचिव होंगे। आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा और जरूरी होने पर सरकार को अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय सुझबुझ का ध्यान रखेगा, ताकि सरकारी खजाने में विकास और जनकल्याण के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता भी बनी रहे।

क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निर्णायक मोड़ साबित होगी

लम्बे अर्से बाद 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के बुसान के एशिया पसैफिक कोऑपरेशन समिट में दोनों की मुलाकात प्रस्तावित है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में 30 अक्टूबर, 2025 को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में होने वाली मुलाकात वैश्विक व्यवस्था में एक निर्णायक क्षण साबित हो सकती है। व्यापारिक रित्तों में तनाव, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक बदलावों के बीच कई वर्षों बाद दोनों की आमने-सामने वार्ता हो रही है।

दांव बहुत बड़ा है। अमेरिका ने चीन के सामान पर 155 प्रतिशत तक के शुल्क लगाने की धमकी दी है, अगर नया व्यापार समझौता नहीं होता है तो, जबकि बीजिंग ने मुख्य प्रौद्योगिकियों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर नियंत्रण कर लिया है। इन कदमों ने

- यह मुलाकात एशिया में नया शक्ति संतुलन पैदा कर सकती है, जो भारतीय कूटनीति की कड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।

- अगर, अमेरिका व चीन में समझौता होता है तो भारत के लिए इसका प्रभाव आर्थिक और सामरिक दोनों होने की संभावना है। वैकल्पिक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की स्थिति कमजोर पड़ सकती है। यही नहीं, तब चीन सामरिक मसलों पर भारत पर हावी होने की कोशिश कर सकता है।

- अगर, अमेरिका व चीन में समझौता हुआ तो भारत को दोनों खेमों में अपनी न केवल स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी, बल्कि, दोनों खेमों के लिए जरूरी भी बने रहना होगा।

वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को हिला दिया है और बाजारों को अस्थिर कर दिया है। उम्मीद है कि व्यापार से परे, ट्रंप और शी संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ताइवान और समुद्री विवादों से

लेकर चीन के रूस के साथ ऊर्जा संबंधों तक सभी मसलों पर वार्ता करेंगे। बुसान में दोनों नेताओं के लिए यह एक अवसर है अपने बढ़ते प्रतिद्वंदी संबंधों को फिर से स्थापित करने का या कम से कम पुनः

समायोजित करने का। भारत के लिए, इसका प्रभाव आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अमेरिका और चीन के बीच किसी भी समझौते से वैश्विक शुल्क और प्रौद्योगिकी प्रवाह फिर से आकार ले सकते हैं, जिससे भारत को अपनी सोर्सिंग और निर्यात रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अगर तनाव कम होते हैं, तो भारत की वैकल्पिक निर्माण केंद्र के रूप में स्थिति कमजोर हो सकती है। यदि तनाव बढ़ते हैं, तो भारत को लाभ हो सकता है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण को बढ़ावा देंगी।

यह मुलाकात एक व्यापक प्रतीकात्मक भी रखती है। यह उस दुनिया में हो रही है, जो टूटे हुए व्यापारिक गुटों, फिर से उभरते राष्ट्रीयतावाद और प्रौद्योगिकी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साइकलोन ‘मोंथा’ आंध्र पहुँचा

चेन्नई, 28 अक्टूबर। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार शाम आंध्र प्रदेश तट से टकराना शुरू हो गया है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) चेन्नई की निदेशक बी. अमुधा ने बताया कि तूफान के तट से टकराने की प्रक्रिया (लैंडफॉल) शुरू हो चुकी है और इसे पूर्ण रूप से तट पार करने में तीन से चार घंटे का समय लगेगा।

उन्होंने बताया कि मोंथा बीते छह घंटों में लगभग 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। और आज शाम साढ़े पाँच बजे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केन्द्रित था।

मौसम विभाग (आईएमडी) ने तटीय आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना, तमिलनाडू में और महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात के कारण बारिश शुरू हो गई है और प्रशासन ने एहतियात बरतने को कहा है।

बांग्लादेश ने पाकिस्तानी जनरल को जो नक्शा भेंट किया है, उसमें नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और बिहार को भी ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया है

पाकिस्तान के जनरल निरंतर बाँग्लादेश की यात्राएँ कर रहे हैं, आपसी सहयोग की कसमें खा रहे हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की भूराजनैतिक स्थिति में एक खतरनाक मोड़ आ गया है। सीमा पार की कड़ियाँ अब स्पष्ट रूप से मजबूत हो रही हैं, जो किसी भी टकराव की स्थिति में क्षेत्रीय संघर्षों को और बढ़ाने वाले कारक बन सकती हैं। विशेष रूप से, भारत ने आखिरकार अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को प्रभावी रूप से मजबूत कर लिया है, जबकि पाकिस्तान लगभग एक बार फिर बांग्लादेश के साथ गहराई से जुड़ गया है। इसके परिणामस्वरूप, अगर किसी भी छोटी सी चिंगारी से टकराव भड़कता है, तो अस्थिरता और हिंसा के फैलने की आशंका बहुत बढ़ जाती है।

पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से सीधे बातचीत शुरू कर दी है, और बांग्लादेश खुले तौर

पर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का अपने देश में स्वागत कर रहा है। बांग्लादेश की सेना अब क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के साथ समन्वय कर रही है।

अब सरकार से सरकार और सेना से सेना के स्तर पर सहयोग बढ़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के बीच तालमेल तक पहुँच गया है। इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन दोनों देशों की सरकारों के संरक्षण में एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं।

हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए एक आदान-प्रदान में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान की सेना को एक नक्शा सौंपा है, जिसमें भारत के बड़े हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। अब वे खुलेआम “ग्रेटर बांग्लादेश” का सिद्धांत आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बड़े हिस्से, पश्चिम

- इस्लामिस्ट रेडिकल व टैररिस्ट संस्थाएँ भी नज़दीक आ रही हैं, दोनों सरकारों के प्रश्रय से।
- इन घटनाक्रमों से प्रोत्साहित पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष मुनीर ने भारत को चेतावनी दी है कि अगले युद्ध में हमले केवल सेना के ठिकानों पर ही नहीं होंगे।
- और यह भी दंभ भरा कि अगला इण्डो-पाक युद्ध पूर्व से शुरु होगा और निर्णायक होगा।
- नॉर्थ ईस्ट में भारत की कमजोरी है, चिकन नैक, जो सिलीगुड़ी में है, वह पतला भूमि का टुकड़ा है, उसे अगर काट दिया जाए तो भारत का नॉर्थ ईस्ट से संपर्क खत्म हो जाता है।
- इस परिदृश्य में भारत ने अफगानिस्तान से दोस्ती करके अपनी स्थिति मजबूत की है, जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा।

बंगाल और यहां तक कि बिहार को भी अपना क्षेत्र बताया जा रहा है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और

‘गलती की है तो चुनाव आयोग गिरफ्तार करें’

अररिया, 28 अक्टूबर। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दो राज्यों की मतदाता सूची में उनका नाम होने पर चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस पर मंगलवार को कहा कि बिहार में

- जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने यह टिप्पणी करते हुए आयोग पर सवाल दागा एसआईआर के बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी क्यों मिल रही है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने वाले चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जांच कर सुधार करे और यदि उसे लगता है कि उन्होंने गलती की है तो वह उन्हें गिरफ्तार करे।

किशोर ने कहा कि "एसआईआर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)